भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 508
उत्तर देने की तारीख- 06/02/2025
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदें

†508. डॉ. मन्ना लाल रावत

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन हेतु नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत भाग ख के पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दें तो, किसी भी राज्य चाहे जिसमें अनुसूचित क्षेत्र न हो, उन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग ख के पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति की पद्धति और परिषद के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति; इसकी बैठकों का संचालन और सामान्य रूप से इसकी प्रक्रिया; और अन्य सभी प्रासंगिक मामलों को निर्धारित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकते हैं। तदनुसार, जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के नियम अधिसूचित किए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र वाले 10 (दस) राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में टीएसी का गठन किया गया है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कोई अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उन्होंने भी टीएसी नियम अधिसूचित कर दिए हैं और उनके आधार पर टीएसी का गठन किया है।